संख्या-47/2026/1/1273281/2026/71-1002/48/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष एकेडमिक ब्लाक के नव निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/212, दिनांक 08.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि केसापेक्ष एकेडमिक ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि हेतु रू0 120.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-57/2023/1/296217/2023/71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा रू0 33.12 करोड़, शासनादेश संख्या-110/2023/1/363840/2023/71-1002/15/2022, 07.08.2023 द्वारा रू0 14.88 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-138/2023/1/4095772023/71-1002/15/2022, दिनांक 17.10.2023 द्वारा रू0 28.80 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 76.80 करोड़ (केन्द्रांश रू0 28.80 करोड़ व राज्यांश रू0 48.00 करोड़) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित की गयी है। वर्तमान में महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में धनराशि अवशेष नहीं है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि केअंतर्गत एकेडमिक ब्लाक के नव निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत **रू0 2604.97 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ चार लाख सत्तानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है -

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
2. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
4. प्रायोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6. प्रायोजना निर्माण में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन०एम०सी०) के मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. प्रायोजना प्रस्ताव में लिफ्ट, सबस्टेशन उपकरण, डी०जी०सेट, सी०सी०टी०वी०, इन्टरकॉम सिस्टम आदि की लागत लोक निर्माण विभाग / डी०एस०आर० 2023 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

8. प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 40.00 लाख प्रस्तावित की गयी है। इस हेतु फिलहाल एकमुश्त रू0 30.00 लाख अनुमन्य किया गया है। प्रभाग का मत है कि विस्तृत आगणन उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जाय।

9. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवंपर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्यप्रारम्भ किया जाये।

10. प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-3-414/दस-2025-26-दिनांक 19 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।